

इस विधेयक का टेक्स्ट पृष्ठ 157 और राज्य सचिव की वेबसाइट voterguide.sos.ca.gov पर देखा जा सकता है।

- निर्दिष्ट परियोजना श्रेणियों (जिनमें अधिकांश आवास, परिवहन, जल, स्वास्थ्य, जंगल की आग को कम करने, शैक्षिक सुविधा, इंटरनेट तक पहुँच और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएँ शामिल हैं) के लिए पर्यावरण समीक्षा में तेजी लाने के लिए California पर्यावरण गुणवत्ता अधिनियम (CEQA) में संशोधन करता है। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए, यह विधेयक:
 - सार्वजनिक एजेंसियों के लिए पर्यावरणीय समीक्षा को पूरा करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अंतिम समय सीमाओं को निर्धारित करता है।
 - पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए व्यवहार्य परियोजना विकल्पों की एक श्रृंखला पर विचार करने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों के वर्तमान दायित्व को सीमित करते हुए, पर्यावरणीय प्रभावों की शीघ्र समीक्षा करने की अनुमति देता है।
 - परियोजना अनुमोदनों को चुनौती देने वाले मुकदमों को दायर करने और उनका समाधान करने के लिए अंतिम समय सीमाओं को स्थापित करता है; उन सबूतों, जिन पर अदालतें विचार कर सकती हैं और राहतें जो अदालतें आदेश दे सकती हैं, को सीमित करता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर पड़ने वाले शुद्ध राजकोषीय प्रभाव का विधायी विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- योग्य परियोजनाओं के लिए नई परियोजना समीक्षा और अदालती चुनौती प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए आरंभिक लागतें, जो संभवतः दसियों मिलियन डॉलर की सालाना ऊपरी सीमा में होगी—संभावित रूप से \$100 मिलियन वार्षिक से अधिक। परियोजना आवेदकों और मुकदमा दायर करने वाले लोगों द्वारा भुगतान की गई फीस आंशिक रूप से इन लागतों की पूर्ति करेगी।
- लंबी अवधि में, राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए अनिश्चित, लेकिन संभावित रूप से अधिक महत्वपूर्ण सकारात्मक या नकारात्मक राजकोषीय प्रभाव। समग्र प्रभाव, आंशिक रूप से, इस बात पर निर्भर करता है कि नई प्रक्रियाएँ, बनने वाली योग्य परियोजनाओं की संख्या को कैसे बदलती हैं और क्या उन परियोजनाओं के अलग-अलग पर्यावरणीय प्रभाव हैं।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

परिप्रेक्ष्य

राज्य कानून के तहत सरकारी एजेंसियों के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा करना आवश्यक है। राज्य और स्थानीय सरकारी एजेंसियाँ कुछ परियोजनाओं के निर्माण से पहले उनकी समीक्षा और मंजूरी देने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। इस प्रक्रिया के तहत, California पर्यावरण गुणवत्ता अधिनियम (CEQA) के अनुसार किसी एजेंसी के लिए किसी परियोजना को मंजूरी देने से पहले यह विचार करना आवश्यक है कि वह परियोजना पर्यावरण पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। CEQA कई प्रकार की सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं पर लागू होता है, जैसे आवासीय

विकास परियोजनाएँ, स्कूल सुविधा-स्थल और राजमार्गों का विस्तार। कुछ अपवाद लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, राज्य कानून सार्वजनिक परिवहन के निकट स्थित कुछ आवासीय विकास परियोजनाओं को CEQA समीक्षा की आवश्यकता से छूट देता है।

CEQA प्रक्रिया कैसे काम करती है। सरकारी एजेंसी सबसे पहले यह निर्धारित करती है कि किसी परियोजना पर CEQA लागू होता है या नहीं। यदि CEQA लागू होता है, तो एजेंसी इसके बाद यह निर्धारित करती है कि क्या परियोजना पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है और क्या परियोजना में छोटे बदलाव करके उन प्रभावों से बचा जा सकता है या उन्हें कम किया जा सकता

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी है

है। यदि छोटे बदलाव करके महत्वपूर्ण प्रभावों से बचा या उन्हें कम नहीं किया जा सकता, तो एजेंसी को अधिक विस्तृत समीक्षा करनी होती है, जिसे पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट (EIR) कहा जाता है। (अधिकांश परियोजनाओं के लिए EIR की आवश्यकता नहीं होती; हालाँकि, बड़ी और जटिल परियोजनाओं के लिए EIR की आवश्यकता कुछ अधिक आम है।) EIR परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का विश्लेषण करती है और उन प्रभावों को कम करने वाले विकल्पों पर विचार करती है। पर्यावरणीय समीक्षा पूरी करने के बाद, एजेंसी यह निर्णय लेती है कि परियोजना को मंजूरी दी जाए या नहीं। इस प्रक्रिया के कुछ चरणों में, सरकारी एजेंसी को परियोजना की पर्यावरणीय समीक्षा के बारे में जनता और अन्य सरकारी एजेंसियों से टिप्पणियाँ माँगनी और उन पर विचार करना आवश्यक होता है।

लोग किसी सरकारी एजेंसी की CEQA समीक्षा को लेकर उसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं। जब कोई सरकारी एजेंसी CEQA समीक्षा पूरी कर लेती है और यह निर्णय ले लेती है कि किसी परियोजना को मंजूरी दी जाए या नहीं, तो जो लोग मानते हैं कि एजेंसी ने CEQA प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया, वे एजेंसी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी परियोजना का विरोध करने वाला व्यक्ति यह तर्क दे सकता है कि पर्यावरणीय विश्लेषण पर्याप्त नहीं था। यदि अदालत यह पाती है कि एजेंसी ने CEQA का सही तरीके से पालन नहीं किया, तो वह पूरी परियोजना को रोक सकती है और एजेंसी को प्रक्रिया के उस हिस्से को ठीक करने का आदेश दे सकती है जिसमें समस्या थी।

कई परियोजनाओं के लिए अन्य मंजूरीयों भी प्राप्त करना आवश्यक होता है। CEQA समीक्षा के अलावा, कई परियोजनाओं को आगे बढ़ने से पहले अन्य स्थानीय और/या राज्य सरकारी एजेंसियों से मंजूरी या परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यवसाय जो स्वास्थ्य क्लीनिक बनाना चाहता है, उसे आगे बढ़ने से पहले स्थानीय सरकार से भूमि उपयोग संबंधी नियमों में बदलाव कराने की आवश्यकता हो सकती है। इसके

अलावा, राज्य एजेंसियों को यह समीक्षा और मंजूरी देने की आवश्यकता हो सकती है कि परियोजना से वन्यजीवों की कुछ प्रजातियों और पानी की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

प्रस्थापना

प्रस्ताव 45 कुछ प्रकार की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए नई प्रक्रियाएँ बनाता है, जिन्हें यह “अत्यावश्यक” के रूप में परिभाषित करता है। चित्र 1 में उन परियोजनाओं के प्रकारों की सूची दी गई है जो नई प्रक्रियाओं के लिए योग्य हैं। यह प्रस्ताव (1) CEQA समीक्षा, परमिट और अदालती चुनौतियों के लिए समय-सीमाओं को सख्त करता है; (2) CEQA समीक्षा प्रक्रिया के कुछ हिस्सों में बदलाव करता है; और (3) CEQA मुकदमों के लिए अदालत की समीक्षा प्रक्रिया में बदलाव करता है। यह प्रस्ताव योग्य परियोजनाओं के आवेदकों को नई प्रक्रियाओं या मौजूदा प्रक्रियाओं में से किसी एक का उपयोग करने का विकल्प देता है।

चित्र 1

प्रस्ताव 45 की नई प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए योग्य परियोजनाओं के प्रकार

- आवास।
- जल प्रणाली (डेल्टा जल परिवहन सुविधा-स्थलों को शामिल न करते हुए)।
- स्वच्छ ऊर्जा (परमाणु ऊर्जा को शामिल न करते हुए)।
- स्वास्थ्य सुविधा-स्थल, क्लिनिक और चिकित्सा कार्यालय भवन।
- अग्निशमन, पुलिस और शेरिफ स्टेशन।
- जंगल में लगने वाली आग के जोखिम में कमी।
- ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक पहुँच।
- शिक्षा सुविधा-स्थल।
- परिवहन (हाई-स्पीड रेल को शामिल न करते हुए)।

योग्य परियोजनाओं की समीक्षा और अदालती चुनौतियों के लिए समय-सीमाओं को सख्त करता है। प्रस्ताव 45 राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा CEQA तथा परमिट संबंधी समीक्षा करने के लिए अधिक बाध्यकारी समय-सीमाएँ निर्धारित करता है। इनमें यह निर्धारित करने की समय-सीमा शामिल है कि परियोजना का आवेदन पूरा है या नहीं, EIR को पूरा करने की समय-सीमा और अन्य प्रकार

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी है

की मंजूरीयाँ तथा परमिट देने की समय-सीमाएँ। उदाहरण के लिए, यदि कोई एजेंसी EIR को पूरा करने के लिए 365 कार्य-दिवस की समय-सीमा का पालन नहीं करती है, तो प्रस्ताव 45 आवेदक को एजेंसी के समक्ष सुनवाई का अनुरोध करने—और संभावित रूप से अदालत में मुकदमा दायर करने—की अनुमति देता है। यह प्रस्ताव कानूनी चुनौतियों का निपटारा करने के लिए अदालतों के लिए भी एक समय-सीमा निर्धारित करता है।

योग्य परियोजनाओं के लिए CEQA समीक्षा में बदलाव करता है। योग्य परियोजनाओं के लिए, प्रस्ताव 45 CEQA समीक्षा प्रक्रिया में कई बदलाव करता है, जिनमें शामिल हैं:

- **आवेदन प्रक्रिया।** सरकारी एजेंसी के लिए यह आवश्यक बनाता है कि आवेदन जमा किए जाने से पहले वह उन सभी जानकारीयों को स्पष्ट करे जिन्हें आवेदन में शामिल किया जाना आवश्यक है। (मौजूदा कानून एजेंसियों को बार-बार अतिरिक्त जानकारी माँगने या परियोजना में बदलाव करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है।)
- **पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन कैसे किया जाता है।** एजेंसी के लिए यह आवश्यक बनाता है कि वह परियोजना का आवेदन जमा किए जाने के समय लागू कानूनों और मानकों के आधार पर संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करे। (मौजूदा कानून एजेंसी को EIR तैयार करते समय नई जानकारी पर विचार करने और अपने समीक्षा मानकों में संशोधन करने की अनुमति देता है।)
- **परियोजना के विकल्प।** आवेदक को एजेंसी के विचार के लिए परियोजना का केवल एक विकल्प तैयार करने की अनुमति देता है। (मौजूदा कानून के तहत आवेदक के बजाय एजेंसी के लिए ऐसे कई परियोजना विकल्प तैयार करना और उन पर विचार करना आवश्यक है, जो पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर सकते हैं।)

- **मूल निवासी जनजातियों के साथ परामर्श।** एजेंसी और आवेदक के लिए यह आवश्यक बनाता है कि वे परियोजना के बारे में केवल California की उन मूल निवासी जनजातियों के साथ परामर्श करें जिन्हें संघीय सरकार द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। (मौजूदा कानून के तहत अधिक व्यापक श्रेणी की जनजातियों के साथ परामर्श करना आवश्यक है।)
- **सार्वजनिक टिप्पणी की अवधि।** यह तय करता है कि एजेंसी प्रोजेक्ट के बारे में जनता और दूसरी सरकारी एजेंसियों से कितने समय तक सुझाव या राय ले सकती है। (मौजूदा कानून पब्लिक रिव्यू के लिए—कम से कम दिनों की संख्या तय करता है—ज़्यादा से ज़्यादा नहीं।)

योग्य परियोजनाओं को दी गई चुनौतियों की अदालतों द्वारा समीक्षा किए जाने के तरीके में बदलाव करता है। जब कोई व्यक्ति किसी योग्य परियोजना को सरकारी एजेंसी द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देता है, तो प्रस्ताव 45 अदालत की समीक्षा प्रक्रिया में कई बदलाव करता है। उदाहरण के लिए, यह CEQA मुकदमों में अदालत द्वारा विचार किए जा सकने वाले विषयों के दायरे को सीमित करता है। यदि अदालत यह पाती है कि एजेंसी ने CEQA का सही तरीके से पालन नहीं किया, तो यह प्रस्ताव अदालत को पूरी परियोजना रोकने से भी बचाता है। इसके बजाय, जब तक एजेंसी समस्या को ठीक करती है, अदालत परियोजना के केवल उस हिस्से को रोक सकती है जिसकी पर्यावरणीय समीक्षा CEQA के अनुरूप नहीं थी।

राजकोषीय प्रभाव

राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए प्रारंभिक लागतें। पहले कई वर्षों के दौरान, प्रस्ताव 45 से राज्य और स्थानीय सरकारों की लागतें बढ़ने की संभावना है, जिसमें राज्य की अदालतें भी शामिल हैं। इन लागतों के प्रति वर्ष कई

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी है

मिलियन डॉलर के ऊपरी दायरे में होने की संभावना है और ये संभावित रूप से प्रति वर्ष **\$100 मिलियन डॉलर से अधिक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए**, राज्य और स्थानीय सरकारों को योग्य परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा के लिए नए दिशानिर्देश और मानक तैयार करने, अधिक सख्त समय-सीमाओं का पालन करने और अदालती चुनौतियों से निपटने के लिए लागतें उठानी पड़ेंगी। परियोजना के आवेदकों और मुकदमे दायर करने वाले लोगों द्वारा दिए जाने वाले शुल्क से इनमें से कुछ लागतें पूरी होंगी। इस प्रारंभिक अवधि के बाद, जहाँ कुछ लागतें जारी रह सकती हैं, वहीं अन्य लागतों में समय के साथ कमी आने की संभावना है। उदाहरण के लिए, अदालतों द्वारा CEQA मुकदमों की समीक्षा करने के तरीके में किए गए बदलावों के कारण भविष्य में कम लोग मुकदमे दायर कर सकते हैं, जिससे दीर्घकाल में एजेंसियों और राज्य की अदालतों की लागतें कम हो सकती है।

दीर्घकाल में, राजकोषीय प्रभाव अनिश्चित हैं, लेकिन संभावित रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। योग्य परियोजनाओं के लिए परियोजना समीक्षा और अदालती चुनौती की प्रक्रियाओं में प्रस्ताव 45 द्वारा किए गए बदलावों से राज्य और स्थानीय सरकारों पर विभिन्न राजकोषीय प्रभाव पड़ सकते हैं। इन बदलावों का समग्र राजकोषीय प्रभाव—सकारात्मक या नकारात्मक—अनिश्चित है, लेकिन यह निकट अवधि के प्रभावों से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, दो ऐसे प्रभाव जिनका महत्वपूर्ण लेकिन अनिश्चित असर हो सकता है:

- **अधिक परियोजनाएँ और तेज़ समय-सीमा।** जिस हद तक प्रस्ताव 45 द्वारा परियोजना समीक्षा और अदालती चुनौती की प्रक्रियाओं में किए गए बदलावों के कारण

योग्य सार्वजनिक परियोजनाओं का निर्माण अधिक तेज़ी से होता है, राज्य और स्थानीय सरकारों की परियोजना लागत कम होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, यदि प्रस्ताव के बदलावों के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर अधिक परियोजनाएँ पूरी होती हैं, तो इससे टैक्स राजस्व में वृद्धि हो सकती है, जैसे संपत्ति टैक्स से मिलने वाले राजस्व।

- **नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव।** जिस हद तक प्रस्ताव 45 द्वारा परियोजना समीक्षा और अदालती चुनौती की प्रक्रियाओं में किए गए बदलावों के कारण ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी मिलती है जिनके नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं और जिन्हें अन्यथा मंजूरी नहीं मिलती, उन प्रभावों से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों को अधिक लागत उठानी पड़ सकती है।

मुख्य रूप से इस विधेयक का समर्थन या विरोध करने के लिए गठित समितियों की सूची के लिए sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2026-ballot-measure-contribution-totals पर जाएँ।

समिति के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं तक पहुंचने के लिए fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html पर जाएँ।